भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2877

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

पीवीटीजी के लिए आवासन और शिक्षा

†2877. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रुप से वंचित जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए स्वीकृत आवासन और शैक्षिक कार्यक्रमों को पूर्ण रुप से कार्यान्वित किया है और क्या चेन्चस जनजाति के लिए 200 आवासन इकाइयों और 50 आदर्श जीपी विद्यालयों का विनिर्माण भी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) पीवीटीजी आवासन परियोजनाओं के लिए आवंटित 5032.5 लाख रुपये की राशि के उपयोग की क्या स्थिति है;

(घ) क्या हाल के पत्राचार के अनुसार 4524.38 लाख रुपये जारी नहीं किए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन लंबित निधि को जारी किए जाने और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किए जाने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(दुर्गादास उइके)

(क) से (ङ): पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय "पीवीटीजी के विकास" की योजना को क्रियान्वित (लागू) कर रहा था, जिसमें संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत, स्वीकृत परियोजनाओं/गतिविधियों का निष्पादन

और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, उक्त योजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुमोदन दिए गए थे:

क्र.सं.	**योजना**	**पीएसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1	चेन्चस के लिए आवास कार्यक्रम (कुल: 200 इकाइयां: इकाई लागत 4.00 लाख रुपये)	800.00
2	पीवीटीजी बस्तियों में मॉडल जीपी स्कूल कुल इकाइयाँ-50 (4.00 लाख की दर से)	200.00
3	पीवीटीजी के लिए घरों का निर्माण (कुल 2013 इकाइयां; इकाई लागत 2.50 लाख रुपये)	5032.50
	कुल	**6032.50**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, तेलंगाना राज्य सरकार को निधियां अनुमोदित की गई और एसएनए प्रक्रिया के अनुसार 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को अनुमोदित राशि का 25% अर्थात् 1508.125 लाख रुपये जारी किए गए। तेलंगाना राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सभी कार्य निष्पादित कर दिए गए हैं और उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं और पीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार, आज की तारीख तक राज्य के पास 97.97 लाख रुपये का एसएनए शेष है। राज्य सरकार को 4524.375 लाख रुपये की प्रतिबद्ध देनदारियों की आगे की रिहाई परियोजना को मंजूरी देते समय राज्य सरकार के लिए पीएसी द्वारा निर्धारित शर्तों और एसएनए प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन है।

*****